

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास में मुक्त शैक्षिक संसाधनों (ओईआर) की भूमिका : एक अध्ययन

¹डा० अंजू सिंह

¹प्रोफेसर अर्थशास्त्र, सी० के० बा० बैजनाथ राजकीय स्ना० महाविद्यालय, हरख, बाराबंकी

Abstract

अमृत काल में युवा शक्ति हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। उनके शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार सृजन, अनुसंधान विकास एवं डिजिटल बुनियादि ढांचे को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान (2023–24 के) बजट में उच्च शिक्षा के लिए ₹० 44904.62 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुक्त शैक्षिक संसाधनों (OER) युवाओं या शिक्षार्थियों को उनके वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करते हैं। यह पाठ्य पुस्तकों और अन्य पाठ्यचर्या सामग्री की लागत को शून्य करके जनसांख्यिकीय विभाजन को पाटने एवं कौशल विकास करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। इसका विकास और प्रचार अक्सर वैकल्पिक उच्च उन्नत शैक्षिक प्रतिमान प्रदान करने की इच्छा से प्रेरित होता है। यह सीखने का अवसर एवं अनुसंधान सामग्री प्रदान करता है जो खुले लाइसेंस के तहत जारी किए गए हैं और बिना किसी लागत के उपयोग करने की अनुमति देते हैं। वंचित समुदायों के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण है जिनके पास पारंपरिक शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच की कमी होती है। ऐसे शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर किसी भी क्षेत्र में नया प्रतिमान बनाने व कौशल विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत है।

मुख्य शब्द— कौशल विकास, ओईआर, जनसांख्यिकीय लाभांश, अनुसंधान, ऑनलाइन शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा आदि।

Introduction

अध्ययन का उद्देश्य विश्लेषणात्मक है जिसमें वांचित या निम्न समुदाय के लोग जिनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण वे पारंपरिक गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच नहीं पाते। ऐसे शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराकर उनमें क्षमता व कौशल का विकास कर समाज में उन्हें नया प्रतिमान बनाने का अनूठा अवसर प्रदान करना है। समकों का संकलन विभिन्न समचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन एवं इंटरनेट के संसाधनों द्वारा किया गया है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष की अवधि को अमृत काल की संज्ञा दी गयी है जिसमें विकास के लिए नया रोडमैप पेश किया गया है। जिसका उद्देश्य सामान्य नागरिकों के जीवन को समृद्ध बनाकर गाँव व शहरों के बीच बनी खाई को पाटना है। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्पना को साकार करना है। इस वर्ष के बजट में सरकार ने युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया है। किसी भी क्षेत्र में युवाओं का योगदान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। भारत में युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास एवं बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक भारत दुनिया का ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। 2018–19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश वर्ष 2041 के आस-पास अपने चरम पर होगा जब कार्यशील जनसंख्या (20–59 वर्ष) की आबादी की हिस्सेदारी 59 फीसदी तक पहुँचने का अनुमान है। यह भारत के आर्थिक विकास के लिए वृहद सम्भावनाओं के द्वार खोलता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास क्षमता में जो बदलाव आता है वह देश के युवा वर्ग की संख्या पर आधारित होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। जापान की अर्थव्यवस्था सबसे पहले इसका अनुभव और विश्लेषण किया और पाया कि वहाँ के आर्थिक विकास की तेज रफ्तार जनसांख्यिकीय लाभांश की वजह से (1964 से 2004) रही। 1964 से 1974 दस वर्षों में से पाँच वर्षों में विकास दर 10 फीसदी से अधिक रही है। उसके बाद के दो वर्षों में 8 फीसदी और 1 वर्ष में 6 फीसदी और उसके बाद के वर्षों में 5 फीसदी रही है। चीन (1994 से 2012) 1994 से इस चरण में प्रवेश किया और 18 वर्षों में से 16 वर्षों में चीन की वृद्धि दर 8 फीसदी से अधिक एवं 2 वर्षों में 8 फीसदी से कम रही है।

भारत में यह चरण (2018–2055) 2018 से आया है जो 37 वर्षों का होगा। यूनोइटेड नेशन पापुलेशन फण्ड (यू0एन0एफ0पी0ओ0) ने अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के जरिए हम इस चरण में आर्थिक विकास की दर में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती निम्न या वंचित समुदाय के युवा वर्ग जिन्हें पारंपरिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है उन्हें शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराना है। मुक्त शैक्षिक संसाधन (OER) इस चुनौती को दूर करने में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों परिवेशों में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चा हाईस्कूल तक की शिक्षा पूरी करें और कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ें। मैसिव ओपन आनलाइन कोर्सेस (MOOCS) के कार्यान्वयन के साथ-साथ स्कूल पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण और ओपन डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के योग्य कार्यबल के सृजन में आगे और योगदान कर सकती है। वैश्वीकरण के दौर में खुले शैक्षिक संसाधन वंचित समुदायों के शिक्षार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जिनके पास पारंपरिक शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच की कमी होती है। भारत में जहाँ अधिकांश शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास पारंपरिक शैक्षिक संसाधनों के भुगतान के लिए पर्याप्त वित्तीय, साधन उपलब्ध नहीं होते वहाँ ओ0ई0आर0 डिजिटल विभाजन को पाटने एवं शिक्षा तक समान पहुँच को बढ़ावा देने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। ऐसे युवा जिन्हें पूरे दिन आर्थिक कारणवश शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिलता उन व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में ओ0ई0आर0 को अनुकूलित किया जा सकता है। शिक्षार्थी अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद भी जीवन पर्यन्त ओ0ई0आर0 को प्रयोग जारी रख सकता है और किसी भी विषय में अपनी समझ और कौशल को मजबूत करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ जुड़ सकता है। यह व्यवहारिक शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित करता है जिससे वे कौशल ग्रहण कर अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। कौशल विकास में खुले संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की गयी है वे निम्नत हैं:—

- प्रौद्योगिकी संवर्द्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPTEL) जो इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में मुक्त आलनाइन पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र प्रदान करता है। वर्तमान में इसके अन्तर्गत 5000 से अधिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है जिसमें 2.7 करोड़ से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं। 80 से ज्यादा पंजीकृत लोग उद्योगों से भी जुड़े हुए हैं। यह भारत में सबसे बड़े ओ0ई0आर0 प्लेटफार्मों में से एक है।
- स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है जहाँ कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक के कक्षाओं का संचालन होता है। 3 करोड़ लोग इसमें पंजीकृत हैं जिसमें 300 आनलाईन कोर्सेस शामिल हैं। यह 1000 से अधिक संस्थानों से पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कोर्स के खत्म होने पर जो क्रेडिट छात्र-छात्राओं को प्रदान किए जाते हैं वे अभी 288 विश्वविद्यालयों में मान्य हैं।
- नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (NDLI) यह भी शिक्षा मंत्रालय की पहल है जिसकी संख्या 2019 में 4.58 करोड़ थी जो 2023 में बढ़कर 9.4 करोड़ से ज्यादा हो गयी है। यहाँ कई भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें उपलब्ध हैं। मोबाइल एप के माध्यम से भी यह सुविधा प्रदान की गयी है।
- ई0पी0जी0 पाठशाला जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की एक पहल है जहाँ 2300 से अधिक ई-पुस्तकों, ई-पत्रिकाओं व 19000 से ज्यादा विडियो एवं अन्य शैक्षिक संसाधनों को कई भाषाओं में उपलब्ध कराती है। यह 70 से अधिक विषयों में संसाधन प्रदान करते हैं। यू-ट्यूब व पी0डी0एफ0 के जरिए भी शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
- मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCS) भारत में कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने इंजीनियरिंग, प्रबंधन और मानविकी सहित कई विषयों में बड़े पैमाने पर मुक्त आनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।
- ओपन एजुकेशन रिसोर्स फण्ड (OERF) शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी फंडिंग पहल है जो OER के विकास के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल क्षेत्र में युवाओं को दक्ष बनाने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्रशिक्षण के लिए आईगॉट कर्मयोगी नायक एक प्लेटफार्म शुरू किया है जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशल विकास करने के लिए और लोक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने का अवसर मिलेगा। इसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित हो रहे हैं जो मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करेगा। इसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे।

ओ0ई0आर0 के संभावित लाभों के बावजूद भारत में उनके कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियाँ हैं। जिसमें बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) मुख्य चुनौती है। जहाँ आज भी 64% फीसदी जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जहाँ 29% फीसदी लोगों के पास इंटरनेट सुविधा है। हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर और स्मार्टफोन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या

में केवल 65 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। यह डिजिटल विभाजन वंचित समुदायों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

- डिजिटल साक्षरता की कमी: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के रिपोर्ट के अनुसार शहरी आबादी के 61% की तुलना में ग्रामीण आबादी का केवल 24% कम्प्यूटर साक्षर है। यह उन शिक्षार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- भाषा बाधाएँ: इसके अन्तर्गत अधिकांश शिक्षण सामग्री अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है जो शिक्षार्थियों के लिए बाधा बनती है। देश में 1600 से अधिक भाषाएँ बाली जाती हैं। जबकि स्थानीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों के अनुवाद को बढ़ावा देने का प्रयास होना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम को आसानी से अपनी भाषा में समझा सके।
- स्थिरता: ओईआर शिक्षकों और पाठ्य सामग्री निर्माताओं के स्वैच्छिक योगदान पर भरोसा करते हैं जो लंबी अवधि तक बने रहने व गुणवक्ता को बनाएँ रखने में चुनौती बन सकते हैं। अतः इसमें स्थिरता लाने के लिए ओईआर के लिए स्थायी वित्त पोषण प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे ये लंबे समय तक उपलब्ध और सुलभ हो।
- बौद्धिक संपदा अधिकार: ओईआर के क्रियान्वयन में एक चुनौती बौद्धिक संपदा अधिकार का है। ओईआर के अन्तर्गत संसाधन स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं। अतः कॉपीराइट का उल्लंघन की चिंता हो सकती है। जिसके लिए क्रियेटिव कॉमन्स लाइसेंस की व्यवस्था की गयी है।
- गुणवक्ता नियंत्रण: ओईआर के जरिये जो भी संसाधन उपलब्ध है उनके सटीक गुणवक्ता और प्रासंगिकता की जाँच की आवश्यकता है क्योंकि बिना जाँच के गलत या पुरानी जानकारी भी संसाधन में शामिल हो जाती है। जो उनके सीखने के परिणामों में नकारात्मक सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए ग्लोबल लर्निंग क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम (GLQAS) की व्यवस्था की गयी है।

इस प्रकार इन चुनौतियों को दूर करके युवाओं को सशक्त बनाने, रोजगार के घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान करने के लिए एवं युवाओं का कौशल विकास करने में मुक्त शैक्षिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और दुनिया के सामने एक मानक बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ—

1. भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता का उपयोग, इकॉनामिक टाइम्स, 26 दिसम्बर 2022
- 2- Open Educational Resources for k-12 education in india. Central square foundation concept paper, M.H.R.D. 13-14 August 2013
- 3- nptel.ac.in
- 4- With 3 crore enrolments, swayam tops other elearning platforms- Time of india 11 Feb. 2023
- 5- <http://ndl.iit.ac.in>
- 6- epgp.inflibnet.ac.in